पटना पटना, शुक्रवार, 21 जनवरी, 2011

हिन्दुस्तान 6

वेंडर नीति अगले वित्तीय वर्ष में : मंत्री

वेंडरों के लिए लागू होगी स्वास्थ्य योजना : अश्विनी वेंडर्स दिवस पर नासवी के बैनर तले वेंडर सम्मेलन, वेंडरों ने भेंट की सब्जियों की टोकरी

वरीय संवाददाता

पटना

राज्य सरकार अगले वित्तीय वर्ष में फुटपाथी दुकानदारों के लिए वेंडर नीति लागू करेगी। इस नीति के तहत मिलने वाली सारी सुविधाएं वेंडरों को मुहैया करायी जाएंगी। इसके लागू होने के बाद वेंडरों के लिए स्वास्थ्य योजना का भी लाभ मिलेगा।

वेंडर्स दिवस पर एसके मेमोरियल हॉल में गुरुवार को नासवी की ओर से आयोजित राज्यस्तरीय वेंडर सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए नगर विकास मंत्री प्रेम कुमार और स्वास्थ्य मंत्री अश्विनी कुमार चौबे ने यह घोषणाएं की। वेंडरों ने अनोखे ढंग से मुख्य अतिथियों का स्वागत किया। टोकरी में सब्जी लेकर आयी महिलाओं ने सभी अतिथियों को भेंट किया। नगर विकास मंत्री ने कहा कि वेंडर नीति के लिए सरकारी स्तर पर कवायद शुरू कर दी गयी है। नगर निगम के अधिकारियों को हिदायत दी गयी है कि वे अपने-अपने क्षेत्रों में वेंडरों की पहचान करें ताकि जल्द से जल्द इन्हें निबंधित कर इन्हें सरकारी स्तर पर सुविधाएं दिलायी जा सके। वेंडरों को भगाया नहीं जाएगा इसके लिए वे निश्चिंत रहें। उन्हें व्यवस्थित किया जाएगा ताकि वे भी अपनी रोजी-रोटी व्यवस्थित रूप से कमा सकें।

एसके मेमोरियल हॉल में गुरुवार को आयोजित वेंडर सम्मेलन में वेंडरों के साथ नगर विकास मंत्री प्रेम कुमार, स्वास्थ्य मंत्री अश्विनी चौबे, विधायक अरुण कुमार सिन्हा व अन्य।

सरकार की शहरी गरीबों के लिए चलायी जा रही आवासीय योजना का भी लाभ इन्हें मिल सकेगा। स्वास्थ्यमंत्री श्री चौबे ने कहा कि वेंडर नीति बनने के बाद वेंडरों के लिए स्वास्थ्य योजना शुरू की जाएगी। नगर विकास विभाग की मदद से जगह-जगह वेंडरों के स्वास्थ्य की जांच के लिए शिविर लगाए जाएंगे। उनकी राय में वेंडरों का निबंधन हो जाने के बाद उनकी समस्याएं अपने आप खत्म हो जाएंगी। इस मौके पर राज्यसभा सदस्य अली अनवर, कुम्हरार के विधायक अरुण कुमार सिन्हा, दीघा की विधायक पूनम देवी, दानापुर की विधायक आशा देवी ने भी वेंडरों की समस्या पर रोशनी डाली व भरोसा दिलाया कि सरकार की ओर से उनके कल्याण के लिए योजनाएं शुरू होंगी। ट्रेंड यूनियन नेता चंद्रप्रकाश सिंह, निदान के राकेश त्रिपाठी व संजय कुमार ने भी अपने विचार रखे।

नासवी के कार्यक्रम प्रबंधक रंजीत अभिज्ञान ने एक पांच सूत्री प्रस्ताव पेश किया जिसके तहत राष्ट्रीय फेरी नीति पर अमल करने, शीघ्र कानून बनाने व ऐसे कानून में नेचुरल मार्केट बनाने, सड़क के संपूर्ण हिस्से का 2.5 फीसदी वेंडिंग के लिए छोड़ने , शिकायत निवारण तंत्र बनाने, टाउन वेंडिंग कमेटियों में वेंडरों को उचित प्रतिनिधित्व देने व मानवाधिकार उल्लंघन की घटनाओं में कडी सजा देने का प्रावधान शामिल है। नासवी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद सिंह ने बताया कि राज्य के 28 शहरों में 1.53 लाख वेंडर हैं। पिछले दिनों सरकार की ओर से ठेकेदारी व्यवस्था खत्म किये जाने से वेंडरों को काफी राहत मिली पर समस्याएं और भी हैं। इसके लिए जल्द वेंडर नीति को लागू किया जाए।